ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*561. |The questioner (Shri Nana Desmukh) was absent for answer *vide* page 2 7...*infra]*

Literacy Drive

562. SHRI CM. IBRAHIM: †
DR. KARAN SINGH:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state whether the programmes like Operation Black Board and Adult Literacy Campaign, implemented to give a special thrust to literacy drive, have been given a go by: if not. the details of the schemes being implemented in pursuance of the literacy drive under the Ninth Five Year Plan, the expenditure incurred thereon, so far. and the targets fixed and achieved so far?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT: (DR MURLI MANOHAR JOSHI): A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Regarding Literacy Drive

Government of India has adopted a two-pronged approach to improve literacy in the country.

* Universalisation of Elementary Education through enrolment of all children in 6-14 year age group and reducing drop-out rates.
* Providing functional literacy to non-literates in 15-35 year age group.

List of schemes to support these goals is at Statement I {*see* below)

This includes Operation Black Board, in which estimated expenditure in lXth Plan will be Rs. 1773.3 crore, a step up of about 60% over the VIII* Plan period expenditure of Rs. 1108.7 crore.

The Adult literacy programmes have however been restructured to meet the changing requirement of the sector with the introduction of Continuing Education Scheme during the IXth Five Year Plan.

Government has placed a lot of emphasis in the sector of elementary education to give a push to total literacy in the country.

---

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri C. M. IBRAHIM.

The total expenditure in the field of Elementary Education and Adult Literacy in the last three five year plans has been as follows:

(Rs. in Crores)

Five Year Plan	Expenditure
VTIth	976.74
Vlllth	4724.426
IXlh (Upto 31.3.2001)	11301.09
2001-2002 (B.E.)	4000.00
TOTAL:	15301.09

In pursuance of the literacy drive a new scheme of Sana Shiksha Abhiyan has also been recently approved by the Government. This has a holistic and convergent approach to implement Universalisation of Elementary Education in a mission mode with a clear district focus. The goals of Sana Shiksha Abhiyan are as follows:—

- All the children in school Education Guarantee scheme Centre. Alternate school. 'Back-to-schooL Camp by 2003.
- All children complete five year primary education by 2007.
- All children complete eight years of schooling by 2010.
- Focus on Elementary Education of satisfactory quality with emphasis on education for life.
- Bridge all gender and social gaps at primary stage by 2007 and Elementary Education level by 2010.
- Universal retention by 2010.

Census 2001 (Provisional) has indicated that India has made significant progress in the field of literacy during the last decade. The salient points of the census report on literacy are:

- Literacy rate is 65.38 percent today as against 52.21 percent in 1991.
- The 13.17 percentage points increase in literacy rate is the highest in any decade.

- Also for the first time, absolute number of non-literates has declined by 31.9 million.
- The number of literates has increased by 203.6 million during the decade.
- The gap in Male-Female literacy rates has decreased from 24.8 percentage points in 1991 to 21.7 percentage points in 2001.

National Literacy Mission had received the prestigious Noma Literacy Award in 1999 for outstanding efforts in spreading literacy, creating awareness and demand for literacy. UNESCO has now decided to give Honourable mention of Noma Literacy Prize to Mahila Samakhya Programme for the ar 2001. Mahila Samakhya Programme builds capacities among groups of women and contributes lowards empowerment of women in rural areas, particularly from socially and economically marginalized groups.

Statement-I

Schemes which are being Implemented in the Ninth Plan

ELEMENTARY EDUCATION

1. Operation Blackboard
2. Teacher Education
3. Sana Shiksha Abhiyan
4. Mahila Samakhya
5. District Primary Education Programme
6. Shiksa Karmi
7. Lok Jumbish
8. Non-Formal Education including assistance to VAs for NFE (included in State Sector) / EGS & AIE
9. National Council for Teacher Education

10 Bal Bhawan Society

11 National Programme of Nutritional Support to Primary Education

12. Joint GOI - UN Programme for Primary Education

ADULT EDUCATION

1. Literacy Campaigns and Operation Restoration
2. Continuing Education for Nco-literates
3. Support to Non-Governmental Organisations
4. Jan Shikshan Sansthan

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) in The Chairl

श्री सी.एम.इब्राहीमः माननीय उपसभापति जी, मंत्री जी का उत्तर बहुत अच्छा है। Thank you for the detailed reply on that. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के तहत 79 परसेंट चिल्ड्रिंस,15 और16 साल की एज के अंदर कवर हुए हैं कम्पलीट हंड्रेड परसेंट एनश्योर करने में कितने साल लगेंगे,नंबर वन-1? नंबर 2 क्या कोई स्पेशल इंसेंटिव्स दिए गए हैं जिसके तहत बैकवर्ड क्लास शेडयूल्ड कास्ट, मायनोरिटीज एजुकेशनली बैकवर्ड के बच्चों के लिए स्कीम है ? नंबर-3, रूरल और अर्बन एरिया में यह गैप कितना है अर्थात् कितने शहरी बच्चे इसके अंतर्गत कवर हुए हैं और गांव के एरिया में कितने बच्चे कवर हुए हैं? आपकी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में मैंने देखा है कि आपने लगभग 3 लाख टीचर्स और 2 लाख स्कूल बिल्डिंग्स की व्यवस्था की है। मैं जानना चाहूंगा कि एक किलो मीटर रेडियस के अंदर जहां गांव के बच्चों के लिए स्कूल नहीं है,उन गांव के बच्चों की सुविधा के लिए गवर्नमेंट के पास कोई प्रावधान है और चौथा प्रश्न मेरा यह है कि आपने अपनी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में कहा है कि 18 स्टेट्स को आपने स्पेशल पावर दिए हैं तो वह स्टेट्स कौन कौन से हैं और ये किस आधार पर दिए गए हैं?

डा.मुरली मनोहर जोशीः उपसभाध्यक्ष जी,देश को साक्षर और शिक्षित बनाने की नीति के तहत हमने सर्व शिक्षा अभियान नाम की आयोजना शुरू की है जिसमें हमने 2010 तक देश में पूर्ण साक्षरता की ओर कदम बढ़ाने की बात कही है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए यह सीमा 2015 तक की है,लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसे 2010 तक पूरा करें। उपसभाध्यक्ष जी, विशेष कारण से हमने यह देखा कि अभी जो जनसंख्या के आंकड़े आए हैं, उसमें पुरुषों में लगभग 75.5 प्रतिशत साक्षरता हुई है और महिलाओं में लगभग 54 प्रतिशत हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह गैप थोड़ा अधिक है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों में महिला और पुरुष के बीच का यह अंतर कम हुआ है और महिलाओं में प्रगति पुरुषों से अधिक हुई है । इसे हम और तीव्र कर रहे हैं। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए हमने इस सर्व शिक्षा अभियान में व्यवस्था की है कि प्रत्येक बस्ती में जहां 25 परिवार भी होंगे और अगर गांव वहां स्कूल चाहेगा,

शिक्षा की व्यवस्था चाहेगा तो इस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वहां व्यवस्थाएं की जाएंगी। उपसभाध्यक्ष जी,एजुकेशन गारंटी स्कीम भी कई राज्यों में चल रही है। उसके माध्यम से भी ये काम किए जा रहे हैं। जहां आवश्यकता पड़ी है, सरकार ने इस पर उन्मुक्त भाव से मदद की है। आज तो यह स्कीम ऐसी है जिसमें 85 प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार दे रही है और 15 प्रतिशत राज्य सरकारें दे रही हैं। आगे यह अनुपात 75 और 25 प्रतिशत होगा और उसके आगे 50 और 50 प्रतिशत होगा। मान्यवर,यह पहली स्कीम है कि 50 प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार ने अंत तक, जब तक कि यह कार्यक्रम पूरा नहीं होगा तब तक देने के लिए स्वीकृति दी है और यह स्कीम ऐसी है कि जिसमें प्लानिंग कमीशन ने स्वीकार किया है कि अभी यद्यपि पूरा डॉक्युमेंट नहीं बना है,फिर भी यह दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी चालू रहेगी।

तो इस प्रकार से एक व्यापक स्कीम की जा रही है जो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे आएगी।

आपने माइन्यूरिटीज और ऐसे क्षेत्रों के लिए कहा, तो सरकार की ओर से एस.सी.,एस.टी.और माइन्यूरिटीज की शिक्षा के लिए भी स्कीम्स हैं और जो हमारा सोशियल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय है,वह विशेषकर ऐसे बच्चों के लिए जो अपंग हैं,उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करता है और हमारे टारगेटिड जिले हैं जिनमें हमने यह पता लगाया है कि कहां कितनी मात्रा में एस.सी., एस टी. में शिक्षा की कमी है, उन पर हमारा ज्यादा जोर है, ज्यादा बल है और जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं विभिन्न सरकारों से, उनमें जो जिले छांटे जा रहे हैं, वे जिले इसी रुप में छाटें जा रहे हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी इसी साल हम लोगों ने इस सर्व शिक्षा अभियान में जो नॉन डी.पी.ई.पी 250 जिले थे, उनके लिए प्री-प्रोजेक्ट ऐलोकेशन कर दिए हैं और उसके साथ साथ 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 200 करोड़ रुपये सैंक्शन किया है पूरी ऐक्टिविटी के लिए और यह हमारा निर्णय है कि अक्तूबर, 2001 तक इन सारे प्रोजेक्ट्स को, जो राज्य सरकारें उन्हीं आधारों पर हमें भेजेंगी, उनको हम क्लीअर कर देंगे। तो कुल मिलाकर हमारा प्रयास यही है कि हम इस तरफ आगे जाएं।

जहां तक इस बात का सवाल है कि अरबन और रूरल में कितना गैप है, उसके लिए आप मुझे नोटिस दें, मैं आपको वे निश्चित आंकड़े दे दूंगा, लेकिन अभी हमारा कोई लेटेस्ट सर्वेक्षण नहीं हुआ है, पुराने एक दो सर्वेक्षण हैं, उनके आधार पर ही हम आपको जानकारी दे सकते हैं। लेकिन हम बराबर इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इस रूप में यह अंतराल , यह गैप गांव और शहर, गांव और शहर के साथ साथ महिला और पुरुष और इसके साथ साथ माइन्यूरिटीज , एस.सी., एस.टी तथा अन्य क्षेत्रों का कम हो और 2010 तक हम इसे समान कर लेंगे, यह हमारी योजना है।

श्री सी.एम.इब्राहीमः सर, इस देश में कितने गांव ऐसे हैं जहां एक किलोमीटर के रेडियस में स्कूल और बिल्डिंग नहीं हैं और कितनी रिक्विजिशन उनके लिए चाहिए, क्या आपके पास इसकी जानकारी है, क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई नीति बनाई है? आपके पास क्योंकि गांव की इन्फारमेशन नहीं है, इससे पता लगता है कि सैंट्रल की जितनी मिनिस्ट्रियां हैं, उनका गांव से कितना प्रेम है। एक तरफ आप कहते हैं कि 79 परसैंट हुआ है लेकिन यह 79 परसैंट कहां हुआ है – क्या इसमें सिर्फ सिटी ही सिटी हैं, शहर ही शहर हैं, गांव नहीं हैं?

दूसरा, कितने गांव ऐसे हैं जहां स्कूल की, पढ़ने की सुविधा नहीं है और कितने गांव ऐसे हैं जहां पर कि बिल्डिंग के लिए पैसा मांगा गया है? आपकी मिनिस्ट्री की 2001 की एनयुअल रिपोर्ट में कहा गया है कि लिट्रेसी मिशन में 18 राज्यों को एक विशेष पावर, ग्रेटेस्ट पावर दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि वे राज्य कौन से हैं और पावर देने का क्या क्राइटेरिया है?

डा.मुरली मनोहर जोशीः उपसभाध्यक्ष जी, जहां तक इस बात का सवाल है कि कितने गांव हैं, यह तो एक ऑन गोइंग प्रोसैस है। राज्य सरकारें स्कूल बनाती रहती है, स्कूल बनते रहते हैं और जहां स्कूल बन जाते हैं उसकी सूचना हमारे पास आ जाती है। सामान्य तौर पर यह आंकड़ा राज्य सरकार के पास इक्ट्ठा रहता है और यह काम वे सरकारें ही करती हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारी स्कीम है, उसके अंतर्गत जब हमें उनकी मांग आती है कि हमं यह बिल्डिंग बनानी है, कमरा बनाना है , अध्यापक नियुक्त करने हैं, एक्स्ट्रा अध्यापक नियुक्त करने हैं तो हमारी जो विभिन्न स्कीम्स हैं उनके अंतर्गत हम उन्हें पैसा देते हैं, अध्यापक देते हैं और कमरे की जब मांग आती है तो हम कमरे देते हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। इसमें बाकी और कई शिक्षा के प्रश्न , खासतौर पर जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हैं, उनके बारे में मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि अगर आप नोटिस देंगे या प्रश्न उठाएंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपने प्रश्न तो किया है केवल साक्षरता अभियान पर विशेष जोर देने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लेकिन अगर आप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से बहुत दूर हटते जाएंगे तो मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए भी मुश्किल होगा। इसलिए कृपा करके अगर आप सवाल की परिधि में रहेंगे तो मेरे लिए सुविधा होगी, नहीं तो आप नोटिस दीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे।

SHRI S. B. CHAVAN : Mr. Vice-Chairman, I would like to raise a basic question with regard to the literacy percentage given by the hon. Minister. May I know the basis on which this percentage has been worked out ? According to my information, it is the National Sample Survey which conducts a sample survey; and, on that basis, this figure has been worked out. In order not to remain

complacent. I would like to understand from the hon. Minister whether he is really convinced that the figures that he is giving reflect the reality. This is one thing.

Another thing is about the Operation Black Board. In the remotest areas, a large number of teachers were appointed but. unfortunately, none of those teachers went to those distant places. The teachers tried their level best to remain in towns and cities and the educational establishments were asked to get these excess teachers absorbed in those institutions. This goes against the very purpose for which the "Operation Black Board' Scheme was launched.

These are the two questions on which I would like to have the realistic information.

डा.मुरली मनोहर जोशीः सभापति महोदय, मैंने साक्षरता दरें बताई हैं, ये वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर बताई हैं, उसमें से यह निकला है, सैंसस रिपोर्ट से यह निकला है। जनगणना तो door to door होती है और यह हमारे सैम्पल सर्वे को भी कन्फर्म करती है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत को लगातार 2 बार साक्षरता की दर को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। पहले 1999 में 9वां पुरस्कार मिला और फिर एक साल के अंतराल के बाद फिर से इस बार हमें यह पुरस्कार मिला है। इसके साथ साथ हमने जो सैम्पल सर्वे कराए थे, वे 62 प्रतिशत बोलते थे, जनगणना 65 प्रतिशत से कुछ अधिक बताती है। यह जो 75 प्रतिशत पुरुषों की दर है और 54 प्रतिशत महिलाओं की दर है, यह भी 2001 की जनगणना के आंकड़े हैं। हमारे पास राज्य वार आंकड़े भी हैं कि किस राज्य में क्या प्रगति हुई है। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि कुछ राज्यों ने इस दृष्टि से बहुत प्रगति की है जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में इस दृष्टि से काफी प्रगति हुई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार जो पिछड़े राज्य माने जाते थे, उनमें भी काफी प्रगति हुई है। कुछ राज्यों मे तो साक्षरता की दर 93-94 प्रतिशत तक पहुंची है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा निराशा नहीं रखना चाहिए कि कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि अब शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी उपक्रम के साथ साथ निजी तौर पर भी लोग प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे आ रहे हैं। इसलिए कुल मिलाकर जो प्रयास हो रहा है, वह साक्षरता की दर को बढ़ाने में सहायता दे रहा है। फिर हमारी जो स्कीम्स हैं, वे बराबर इस बारे में फोकस्ड हैं, वे इस बारे में ध्यान दे रही हैं कि कहां गैप है। हमने अभी अपने अधिकारियों को यह आदेश दिए हैं कि आप प्राथमिकता के आधार पर उन जिलों को छाटें और जिलों में भी उन ब्लॉकों को छाटें, जहां शिक्षा की दर सबसे कम है। महोदय , यह जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसमें खास तौर पर इस बात की ताकीद की गई है कि जिन जगहों पर, जिन ब्लाकों में शिक्षा की दर सबसे कम है, उनको छांटें और वहां इस बात को देखें कि विद्यालयों में भर्ती हो और अगर किसी गांव में जैसा मैंने कहा कि 25

परिवार हैं और उनका स्कूल एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, तो हम वहां शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं।

जहां तक अध्यापकों की नियुक्ति और उनके जाने का सवाल है, हमारे पास जो शिकायतें आती हैं, हम उनकी जांच कराते हैं लेकिन यह मुख्य रूप से राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे इसको देखें और मैं माननीय सदस्य से इस बारे में सहमत हूं क्योंकि मैंने कई जगह निरीक्षण किए हैं और यह देखा है कि सूदूरवर्ती क्षेत्रों में लोग नहीं जाते, नियुक्ति होने के बाद भी घर बैठे रहते हैं और कई बार ये स्थानीय आधार पर अपने लिए व्यवस्था कर लेते हैं, कहीं अटैच करा लेते हैं। इसलिए हमने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह व्यवस्था रखी है कि इसमें जो शिक्षक चुने जाएंगे, उनको उसी गांव के लोग चुनेंगे और खुली ग्राम-सभा की बैठक में चुनेंगे और वहीं के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी और यदि वह महिला होगी तो उसे और भी अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय हम राज्य सरकारों से बार-बार यह आग्रह करते हैं कि वे प्राथमिक शिक्षा की देखरेख और उसके प्रबंध का काम यथाशीघ्र पंचायती-राज संस्थाओं के हाथ में दें क्योंकि हमने जो सर्वशिक्षा अभियान चलाया है, उसमें पंचायती-राज संस्थाओं की मुख्य भूमिका है जिला स्तर पर भी और ग्रामीण स्तर पर भी । महोदय प्रदेश स्तर पर भी हम इसे एक संगठन के माध्यम से चलाएंगे और सरकारी तंत्र की जो देर होती है, उसे रोकने के लिए हम इसमें तेजी लाएंगे लेकिन राज्य सरकारें अपने यहां ये अधिकार पंचायती-राज संस्थाओं को नहीं देती हैं, यह कठिनाई भी आती है और जहां पंचायती राज्यों को दिया गया वहां अध्यापकों की तरफ से इसमें बाधा आई और वे इसके बारे में हड़ताल पर चले गए। कुछ राज्यों की सूचना मेरे पास है। इन सबमें अगर एक सार्वजनिक रूप से वातावरण बनाया जाए कि हम पंचायती राज्यों के तहत इस प्राथमिक शिक्षा को सौंपेंगे जैसाकि, हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले था, महात्मा जी ने इस बात को स्पष्ट किया और ऐसी रिपोर्ट है कि पंचायतें हमारे यहां इन सारे कामों को करती थीं, मेरा आग्रह रहता है, अनुरोध रहता है सरकारों से कि जल्दी से जल्दी इस काम को करें। ऐसा करने से ये कठिनाइयां भी दूर होंगी और मैं इससे सहमत हूं कि जो सुदूरवर्ती गांव हैं वहां अध्यापक आएं ।

उपाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : दर्शक दीर्धा में जो टी.वी. कैमरा लगा हुआ है उससे दर्शकों को काफी परेशानी हो रही है। वे चाहें जो डिस्टिंग्विश गैलरी में अपना कैमरा कर सकते हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम हर गांव में स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि वहां के लोग चाहें। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें स्कूल स्वयं ही सब जगह बनाने चाहिए क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जहां 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है और यह भी

हकीकत है कि देहात के लोग अपने बच्चों से काम लेते हैं इसमें की शक नहीं है और इसीलिए उनके मन में स्कूल में भेजने की कोई बहुत बड़ी चाह नहीं रहती क्योंकि वह दिन भर या तो गाय चराएगा, जानवर चराएगा, घास लेगा यह सब काम देहात के लोग करते हैं। यह आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति के कारण करते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि इसको तो अपना कर्त्तव्य मानकर, परम कर्त्तव्य मानकर माननीय मंत्री जी शिक्षा विभाग से हर गांव में स्कूल खुलवाएं।

मेरा 'बी' पार्ट प्रोढ़ शिक्षा के संबंध में है। माननीय मंत्री जी ने साक्षरता के आंकड़े दिए हैं। जिलों में साक्षरता के आंकड़े जो जिलाधिकारी के जरिए से वहां बनाए जाते हैं प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आखिर उसका मापदंड क्या है? अगर कोई हस्ताक्षर भी कर देता है तो जिलाधिकारी वहां पर लिख देता हैं कि प्रौढ़ शिक्षा के जरिए से वह साक्षर हो गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में निश्चित रुप से कोई ऐसी गाइड लाईंस या कोई ऐसे मानक जिलाधिकारियों को भेजने चाहिए कि साक्षरता का पूरा मतलब क्या हो, यह नहीं हो कि केवल वह हस्ताक्षर कर दे और वहां रजिस्टर में दर्ज हो जाता है कि यह साक्षर है। तो ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी से मेरा निवदन है कि क्या वे इस पर विचार करेंगे?

डा. मुरली मनोहर जोशी: उपसभाध्यक्ष जी, जो साक्षरता की दरें आई हैं, हमारी राष्ट्रीय जनगणना के जो मानक हैं उसके अनुसार हमें प्राप्त हुई हैं और इसमें केवल किसी जिलाधिकारी ने लिख दिया है ऐसी बात नहीं है। हमारी कोशिश है कि पहले जिले में जिसको पूर्ण साक्षरता की स्कीम कहते थे टी.एल.सी. वह हम चलाते रहें और उसके बाद जब उसका मूल्यांकन हो कि यहां लोगों को साक्षरता अर्थात केवल हस्ताक्षर करना आवश्यक है और साक्षरता के जो कुछ कम्पोनेंट हैं वह उन्हें प्राप्त हैं, उनका मूल्यांकन हो गया, प्रमाणित हो गया कि हां, यह चला, तो फिर टी.एल.सी. के पश्चात् पी.एल.सी. स्कीम चलाते हैं, पोस्ट लिटरेसी स्कीम, और उसके जिलेवार आंकड़े भी हम दे सकते हैं कि 598 जिले में से केवल 160 जिले बचे हैं जहां टी.एल.सी. भी पूरी नहीं हुई है और ऐसे 272 जिले हैं जहां पी.एल.सी. अर्थात् पोस्ट लिटरेसी केम्पेन चल रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसका मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन की रिपोर्ट आती है। मेरे पास रिपोर्ट है, पी.एल.सी. का भी मूल्यांकन होता है, टी.एल.सी. का भी मूल्यांकन होता है और उसके पश्चात् जहां टी.एल.सी., पी.एल.सी. दोनों हो जाती हैं वहां कंटीन्यूइंग एजूकेशन की स्कीम हम चालू रखते हैं। तो उद्देश्य यह नहीं है कि वह केवल दस्तखत करना सीख लें, बल्कि वह पढ़े, एक प्रमाण पत्र प्राप्त करे। कक्षा का यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सकता तो ओपन स्कूल के माध्यम से प्रमाण पत्र प्राप्त करे। ऐसी सुविधाएं दी गई हैं, दूर-दूर तक उसे हम फैला रहे हैं और उसके बाद वह पी.एल.सी. करे और उसके बाद फिर वह कंटीन्यूइंग एजूकेशन के अंदर आ सकता है। आपका कथन ठीक है लेकिन अब ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कोई एक किलोमीटर या उसके आसपास की दूरी से अधिक स्कूल हो। 98 परसेंट गांव लगभग ऐसे हैं, हमने यह देखा

कि कुछ राज्यों में, कुछ क्षेत्रों में जैसे कि उत्तर पूर्व है या जनजातीय क्षेत्र हैं जहां आबादी छितरी हुई है। वहां हमने नार्म्स को भी ढीला किया है और सर्वशिक्षा अभियान में भी ये नार्म्स ढीले कर दिए गये हैं। उसका उद्देश्य यही है कि सब जगह पर यह मिले। मैंने कहा था कि गर एक किलोमीटर की दूरी में जहां पर स्कूल नहीं है, वहां बस्ती चाहे भले ही 25 या 50 घरों की हो, चाहे लड़के या लड़कियां दोनों कम हों तो भी हम सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से उनको दे रहें हैं और आगे जैसा मैंने निवेदन किया कि अक्तूबर के अंत तक हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो भी हमारे पास आयेंगे हम क्लियर कर देंगे। इसमें हमने यह ध्यान दिया कि सर्वशिक्षा अभियान सीधे गांवों में, सुदूर तक पहुंचे। मैं समझता हूं कि इतनी जानकारी आपके लिए काफी है।

SHRI BACHANI LEKHRAJ : Sir, on 26th January, 2001, there was a devastating earthquake in the State of Gujarat and about nine thousand primary school buildings were completely damaged. The Government of Gujarat had requested the Government of India for assistance, under the Operation Blackboard Scheme. I would like to know from the hon. Minister the amount, that has been sanctioned by the Government of India, under the Operation Blackboard Scheme, to the State of Gujarat. Of the sanctioned amount how much has been given by way of advance, and what is the balance amount that is yet to be released to the Government of Gurajat ? Sir, at present, in so many villages, in seven districts of Gujarat, including Kutch, the students belonging to primary classes are sitting under trees or sitting in tents. Therefore, I would like to know from the hon. Minister how much amount the Government of India has sanctioned or propose to sanction, under the Operation Blackboard Scheme.

डा. मुरली मनोहर जोशी: उपसभाध्यक्ष जी, जैसा मैंने निवेदन किया कि यह आपरेशन ब्लैक बोर्ड और प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित सवाल है। लेकिन हमारी नीति रहती है कि हम इसका इवेल्यूएशन करते हैं। पिछली बार उड़ीसा में ऐसा ही एक प्राकृतिक प्रकोप हुआ था, सुपर साइक्लोन आया था, इसी प्रकार का विध्वंस हुआ था तो सब प्रकार का निरीक्षण होने के बाद हमारे पास जानकारी आई तो हमने 10 हजार विद्यालयों की रचना के लिए उन्हें धन दिया था। गुजरात सरकार से यहां पर ऐसी कोई मांग आई होगी तो उसका इवेल्युएशन हम करेंगे और उसके पश्चात् जो कुछ उसमें से निकलता है वह हम जरुर देने की कोशिश करेंगे। परन्तु मैं यह बता दूं कि हमने 100 करोड़ रुपया गुजरात की सरकार के विश्व विद्यालयों के लिए जहां विध्वंस हुआ था, उनकी बिल्डिंग्स, उनके इक्युपमेंट और उनके छात्रावास बनाने के लिए बिना किसी के मांगे ही दे दिया था। इस रुप में अगर हमारे विभाग के पास कोई मांग आई होगी तो मैं उसका अवश्य परीक्षण करा लूंगा। अन्यथा सम्मानित सदस्य उसको भिजवा दें मैं उसको देख लूंगा।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि हिन्दुस्तान में आजादी के 54 वर्षों के बाद आज भी दुनिया के सबसे अधिक निरक्षर लोग रहते हैं। इसके बावजूद मंत्री जी यह कह रहे हैं कि निराश होने की जरुरत नहीं है। बहरहाल आशा पर ही प्रगति निर्भर है इसलिए हम भी आशान्वित हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति बहुत ही बुरी है और शिक्षा हमारे बच्चों के लिए एक सपना ही रह गया है। इसीलिए नागार्जुन ने कहा था, "चन्दू मैने देखा सपना, इम्तहान में बैठे थे तुम"। उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री जी से मेरा पहला सवाल यह है कि हमारे देश में शिक्षा का समान रुप से विकास नहीं हुआ। बहुत से ऐसे राज्य हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़े हुये हैं। जहां तक बच्चियों की शिक्षा का सवाल है तो स्थिति और भी बदतर है। मेरा सवाल है कि वे राज्य जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, खासकर बालिकाओं के मामले में पिछड़े हुये हैं, उनके लिए आप कौन-सी वृहत्तर योजनायें बना रहे हैं? मेरा दूसरा प्रश्न मंत्री जी के उत्तर से जुड़ा हुआ है। मंत्री जी ने कहा है कि संतोषप्रद गुणवत्ता की प्रारम्भिक शिक्षा पर बल। उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहूंगी कि जब हम संतोपप्रद गुणवत्ता की शिक्षा की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम अपने नागरिकों को जड़ता से मुक्त करेंगे, अंधविश्वास से मुक्त करेंगे और उनकी जिज्ञासा और बढ़े इसकी ओर हम प्रेरित करेंगे। लेकिन क्या मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, विशेषकर शिशु मंदिर के नाम से जो स्कूल चल रहें हैं उनमें हमारे देश की बुनियादी शिक्षा नीति के विरोध में शिक्षा दी जा रही है? ...(**व्यवधान**)...

डा. मुरली मनोहर जोशी: यह इससे जुड़ा हुआ नहीं है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: यह बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं सवाल करने जा रही हूं, क्या यह आपके जहन में आया है? और साथ ही आपने अपने जवाब मैं कहा है कि महिला, पुरुष भेदभाव और सामाजिक अंतरालों को पाटना। जब हम महिला-पुरुष के बीच की बात करते हैं तो सिर्फ संख्या के स्तर पर ही नहीं विषयवस्तु के स्तर पर भी पाटेंगे। आपने जो नया पाठ्यक्रम जारी किया है, उसमें हम यह देखते हैं कि महिला-पुरुष भेदभाव, लैंगिक भेदभाव को बढ़ाने पर बल है। महोदय्, बहुत पहले प्रेमचन्द जी ने कहा था, अगर औरतों के लिए खाना बनाना जरुरी है तो पुरुषों के लिए भी खाना बनाना जरुरी होना चाहिए। आप राष्ट्रीय पाठ्क्रम में लैंगिक भेदभाव को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं चाहूंगी कि इन तमाम प्रश्नों का जवाब मंत्री जी दें।

डा. मुरली मनोहर जोशी: उपसभाध्यक्ष जी, इस मूल प्रश्न से कहीं यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन सम्मानित सदस्या ने यह बात उठाई है तो मैं बहुत साफ बता देना चाहता हूं कि सरकार की ओर से ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव महिला और पुरुषों में रखा जाए और न ही एनसीईआरटी ने जो पाठ्यक्रम का पेपर प्रस्तावित किया है उसमें

एक भी ऐसा शब्द है। मैं नहीं जानता कि बार-बार क्यों इस बात को उठाया जा रहा है जबकि यह बात स्पष्ट कर दी गई है और नेशनल करिकुलम आफ फ्रेम वर्क में यह साफ-साफ लिखा है। आज किसी राज्य सरकार ने, किसी शिक्षाविद् ने एक शब्द नहीं लिखा कि इसमें लैंगिक भेदभाव है।

उपसभाध्यक्ष(श्री सुरेश पचौरी): ठीक है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: दूसरी बात यह कही जा रही है कि देश में बहुत अधिक लोग निरक्षर हैं। यह बात ठीक है कि यह निरक्षरता हमें एक धरोहर में मिली है। यह इस सरकार की देन नहीं है, लेकिन मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि आजादी के इतिहास में पहली बार निरक्षरों की एबसोल्यूट संख्या में तीन करोड़ से अधिक लोगों की संख्या कम हुई है। आज तक कभी एब्सोल्यूट नम्बर आफ लिटरेसी कम नहीं हुई है और जहां तक आशा का सवाल है, हम तो विश्वास के साथ काम करते हैं और मैं सम्मानित सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि...

उपसभाध्यक्ष(श्री सुरेश पचौरी): ठीक है।

डा. मुरली मनोहर जोशी: सरकार पूरी तरह से प्रयत्न कर रही है। इस योजना को हम 2010 तक पूरा कर लेंगे। मैं यह भी बता दूं कि भारत में लगभग 65-66 करोड़ लोग शिक्षित हैं। देश में जो कुछ हुआ है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए केवल उसका निरादर करने से कोई काम नहीं चलता।

SHRI KARTAR SINGH DUGGAL: Sir, I would like to know what concrete steps are being taken to see that the adult literates do not relapse into illiteracy. In my opinion, the only way out is. a national network of libraries. Every panchayat should have a library, stuffed with books, the way our godowns are stuffed with grains these days.

डा. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, इस बारे में, मैं बार-बार सदन को आश्वासन दे रहा हूं कि जो हमारी स्कीम्स हैं, हम इस बात का विश्वास रखते हैं कि जो पोस्ट लिटरेसी कैम्पेन है, उसके आगे जो कंटिन्युइंग एजुकेशन है वह इसी दृष्टि से हैं कि लोग अपनी शिक्षा को जारी रखें। जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से भी इस बात का विश्वास रखा जाता है कि वे पढ़ते रहेंगे और जो कुछ पढ़े उसका उपयोग जीवन में कर सकें। इसलिए उनको वोकेशनल दृष्टि से भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सारी स्कीम्स हैं। जहां तक लोईब्रेरीज का सवाल है, अच्छा सुझाव है और राज्य सरकारों को हम बराबर लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं। साधनों के अनुसार ही हम गावों में अलग से भी लाइब्रेरी रखेंगे। हमारी चेष्टा है कि विद्यालयों में भी लाइब्रेरी हों लेकिन यह साधनों पर निर्भर करता है। जितने साधन हमारे पास उपलब्ध होंगे, उस रफ्तार से हम इसे बढ़ाएंगे।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा: महोदय, मेरा प्रश्न लाइब्रेरी से ही संबंधित है। एक स्कीम,"Scheme for Establishment of Rural Libraries' की घोषणा की गई थी। इस स्कीम को राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के जरिए कार्यान्वित किया जाना था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस स्कीम के अंदर, पिछले वर्ष से ही यह अस्तित्व में है, कितनी राशि आबंटित की गई और गांवों के अंदर कितनी लाइब्रेरीज स्थापित हुईं? मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार लिटरेसी कैम्पेन से इसे जोड़कर इस स्कीम की मूल भावना को, मूल उद्देश्य को दरकिनार कर दिया गया है। इस संबंध में मंत्री महोदय के पास क्या इन्फोर्मेशन है? मेरा दूसरा सवाल यह है कि चूंकि स्कूल में बिल्डिंग्स की बात आई है तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि एम.पी. लैड के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में जो स्कूल बिल्डिंग्स बनी हैं उनके रख-रखाव के लिए क्या केन्द्र सरकार अलग से राशि आवंटित करने पर विचार कर रही है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: उपसभाध्यक्ष जी, यह प्रश्न संबंधित सवाल के संदर्भ में नहीं उठता इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

AFRO-Asian Games

*563. PROF. M. SANKARALINGAM : Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state :

(a) the total expenditure to be incurred on the Afro-Asian games to be held this year;

(b) whether Government would consider holding the games in other major cities, apart from New Delhi;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SUSHREE UMA BHARTI): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Based on the initial estimate*. made by the Indian Olympic Association, a provision of Rs. 30.00 crores for -. upgradation of infrastructure and procurement of equipment and Rs. 20.00 crores for the conduct of the Games has so far been made by the Government. However, an assessment of the additional expenditure likely to be incurred for the Games is being made on the basis of the budget estimates prepared by various committees of the Afro-Asian Games.

(b) No, Sir.